बजट और जनकल्याण

तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 के बजट पेश करने के साथ आर्थिक सुधारों की इबारत लिखी। तब से लेकर अब तक हर बजट की खास बातों पर पेश है एक नजर:

मनमोहन सिंह

1991
- पहली बार सार्वजनिक उपक्रम की 20 फीसद हिस्सेदारी बेचने की घोषणा
- निजी एवं संयुक्त क्षेत्र को म्युचुअल फंड में प्रवेश की इजाजत
- मार्केट रेगुलेटर सेबी का गठन
- कुछ उर्वरकों की कीमतें विनियंत्रित हुई, अन्य की कीमतों में औसतन 30 फीसद वृद्धि। पीडीएस चीनी सब्सिडी खत्म।

1992
- केवल तीन आयकर स्लैब किए गए। दरें बीस, तीस और चालीस प्रतिशत
- छोटे कारोबारियों के लिए पूर्व अनुमानित कर, लांग टर्म कैपिटल गेन्स इंफ्लेशन- इंडेक्स्ड
- सीमा शुल्क की उच्चतम दर घटाकर 110 प्रतिशत

1993

दोहरी विनिमय दर प्रणाली का अंत। मुक्त फ्लोटिंग दर की शुरुआत

1994
- आइएमएफ ऋण का पूर्व भुगतान
- वित्त घाटे के लिए आरबीआइ से सरकार द्वारा कर्ज लेने की सीमा निर्धारित।
- पहली बार सेवा कर लागू।
- सूचीबद्ध और गैरसूचीबद्ध कंपनियों के लिए समान नियम।

1995

बीमा नियामक के गठन की घोषणा। सीमा शुल्क की उच्चतम दर को कम करके पचास फीसद किया गया

पी चिदंबरम

1996
- आयकर के निचले स्लैब की दर घटकर 15 प्रतिशत हुई
- विनिवेश आयोग की स्थापना

1997
- ईपीएफ भागीदारी को 8.33 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया
- फेरा की जगह फेमा का प्रस्ताव
- आयकर की दरें 10, 20 और 30 प्रतिशत तय। काला धन को बाहर निकालने के लिए वीडीआइएस स्कीम। सेवा कर का दायरा बढ़ा

2004
- नरेगा की पूर्ववर्ती काम के बदले अनाज योजना 150 जिलों में लांच
- दो प्रतिशत शिक्षा उपकर लगाया गया
- टेलीकॉम, नागरिक उड्डयन और इंश्योरेंस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि

2005
- नरेगा, एनआरएचम, एनयूआरएम लांच। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम को सर्वव्यापी बनाया गया
- जमा निकासी पर लगाया जाने वाले कर और फ्रिंज बेनेफिट कर का प्रस्ताव

2006

सीमा शुल्क की उच्चतम दर 12.5 प्रतिशत

2007
- सीमा शुल्क की उच्चतम दर घटाकर 10 प्रतिशत की गई
- मैट के दायरे में इंफोटेक क्षेत्र को भी शामिल किया गया

2008
- फ्यूचर एंड ऑप्शन सौदों पर कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का प्रस्ताव
- जमा निकासी पर कर की समाप्ति
- बुनकरों के लिए 60 हजार करोड़ के फार्म लोन की घोषणा। बाद में इसको बढ़ाकर 71 हजार करोड़ किया गया

यशवंत सिन्हा

1998
- डेरीवेटिव्स ट्रेडिंग की शुरुआत
- पीएसयू में सरकारी हिस्सेदारी 26 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
- बड़े लेनदेन के लिए पैन की अनिवार्यता
- एक पेज के सरल फार्म की शुरुआत
- किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत
- राजमार्गों के लिए पेट्रोल पर एक रुपये

मौका आम बजट। सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा। जनकल्याण के लिए नीतियों के सृजन का अवसर। अर्थव्यवस्था की थकान को दूर करने का एक मंच। लंबित आर्थिक सुधारों को लागू करने का एक आधिकारिक दिन।

मायने हम सभी बजट बनाते हैं। अपनी आय के अनुसार कोई प्रतिदिन तो कोई मासिक तो कोई सालाना अपने खर्चों का विवरण तैयार करता है। सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले सालाना आम बजट में कमाई और जनकल्याण के बीच एक तार्किक संतुलन होना जरूरी है। अन्यथा आम जनता के लिए ऐसे मौके बेमानी हो जाएंगे। फिर चाहे सरकार बजट पेश करे या न करे, अपनी गाढ़ी कमाई से टैक्स चुकाने वाली जनता के लिए इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। वैसे भी सरकार बजट के बाद भी चीजों के दाम बढ़ाने से लेकर नीतियों में बदलाव करने तक परहेज नहीं करती है। बदलते भारत में परंपरागत रूप से पेश किए जाने वाले सरकारी आय-व्यय वाले आम बजट से लोगों की आशाएं बदल चुकी हैं।

मकसद बजट का मूल मकसद राजस्व में वृद्धि के संतुलित तरीके खोजना और उस धन का जनकल्याण में इस तरह इस्तेमाल करना जिससे राष्ट्र का समग्र विकास हो। असंतुलन की धूप छांव कहीं न दिखे। अफसोस, हर साल बजट पेश किए जाने के बावजूद खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, गरीबी, बेरोजगारी, समाज ऊर्जा, उद्योग और आधारभूत सुविधाओं जैसे क्षेत्र असंतुलन के शिकार हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऐसे में नए भारत की जरूरतों के मुताबिक आगामी आम बजट पेश किया जाना हम सभी के लिए बड़ा मुद्दा है। आशा है, इस मौके को महज चुनावी बजट न बनाते हुए वित्तमंत्री जी हम सबका ख्याल रखेंगे।

अब देश का एक नया रूप सामने है। इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम बदल चुके हैं। एक बड़ा और सशक्त मध्य वर्ग उभर चुका है। युवा आबादी का ग्राफ ऊपर चढ़ चुका है। ऐसे में परंपरागत रूप से सरकारी आय व्यय के रूप में पेश किए जाने वाले आम बजट की चुनौतियां और उससे लोगों की उम्मीदों ने भी अपना रूप बदल लिया है।

जसवंत सिंह

1999
- शाम के पांच बजे के बजाय पहली बार सुबह 11 बजे बजट की घोषणा
- गोल्ड जमा करने की स्कीम लांच

2000
- 16 फीसद सेनवेट में एक्साइज शामिल
- ग्राम सड़क योजना लांच

2001
- पेट्रोलियम पदार्थों पर सरकारी कीमत नियंत्रण व्यवस्था का अंत
- शिक्षा लोन स्कीम शुरू

2002
- एग्रो मार्केटिंग में उदारीकरण का प्रस्ताव
- राज्य कर्जों को कम करने के उपाय

2003
- राज्यों के लिए कर्ज अदला-बदली नीति। उच्च दर वाले कर्ज को कम दर वाले ऋण में बदलने की अनुमति
- नदी जोड़ परियोजना पर टास्क फोर्स की घोषणा। लाभांश वितरण कर लागू
- लांग टर्म कैपिटन गेन्स टैक्स हटा। बैंकों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर 49 से 74 फीसद किया गया
- बिक्री कर से वैट अपनाने वाले राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति की घोषणा।

प्रणब मुखर्जी

2009
- कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हटा। फर्मों पर लगा फ्रिंज बेनेफिट टैक्स खत्म। न्यूनतम वैकल्पिक कर 15 प्रतिशत हुआ
- सूचीबद्ध कंपनियों में पब्लिक होल्डिंग बढ़ाने की बात

2010
- न्यूनतम वैकल्पिक कर 18 प्रतिशत किया गया
- 40 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य वाली महत्वाकांक्षी विनिवेश योजना की घोषणा

2011
- सस्ते आवास जैसी आम आदमी को लक्षित रियायतें
- गरीबी रेखा से नीचे के लिए सीधे नकदी सब्सिडी स्थानांतरण की घोषणा
- अप्रत्यक्ष करों का रोडमैप, प्रत्यक्ष कर संहिता के लिए डेडलाइन, केवल वेतन वाली आय के लिए आयकर रिटर्न न भरने की व्यवस्था

2012
- सभी स्तरों पर उत्पाद शुल्क की दर में एक से दो फीसद का इजाफा, सेवा शुल्क दो फीसद बढ़ा
- समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन

कैसा हो नए भारत का आम बजट

-हैप्पी पंत
(सीनियर प्रोग्राम कंसल्टेंट, सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटबिलिटी (सीबीजीए))

यदि सरकार समावेशी और संतुलित विकास को लेकर गंभीर है तो अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाने के बजाय बजट का दायरा बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए टैक्स-जीडीपी अनुपात में सुधार के साथ विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिकताओं को भी बदलना होगा। वंचित वर्गों का भी खास ख्याल रखना होगा।

करीब एक दशक से विकास के अधिकांश सेक्टरों में वित्तीय स्रोतों की कमी से उनकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 2.5 प्रतिशत, स्वास्थ्य पर दो, खाद्य सुरक्षा पर एक, सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन पर दो और जल एवं साफ-सफाई पर एक प्रतिशत अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत है। सरकार को अपनी राजस्व नीति में बदलाव करते हुए अतिरिक्त प्राप्तियां जीडीपी का आठ प्रतिशत तक करनी चाहिए।

टैक्स राजस्व के मामले में विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना में हमारी स्थिति काफी खराब है। यहां टैक्स-जीडीपी अनुपात महज 16.6 प्रतिशत है, जबकि अधिकांश जी-20 देशों में यह अनुपात 22-28 प्रतिशत के बीच में है। आने वाले वर्षों में भारत का टैक्स-जीडीपी अनुपात जीडीपी का कम से कम 20 प्रतिशत होना चाहिए। इसके अलावा हमारी टैक्स व्यवस्था अप्रत्यक्ष करों पर काफी हद तक निर्भर है। कुल करों में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा 37.7 प्रतिशत है। कुल मिलाकर इस तरह की कर संरचना प्रगतिशील नहीं है। ऐसे में सरकार को टैक्स राजस्व संग्रह में अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर रहने के बजाय प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। अगर खर्च के लिहाज से देखा जाए तो केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त बजटीय खर्च जीडीपी का 25 प्रतिशत है। यह इस बात को दर्शाता है कि सरकार का देश के भीतर कितना कम हस्तक्षेप है। बजट में कुछ ऐसे क्षेत्रों और आबादी की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है जिनमें देश की करीब 300 सिविल सोसायटी समूहों की चिंताओं को भी शामिल किया गया है।

ताकि बनें ज्ञान के सिरमौर

18 वर्ष की आयु तक सार्वभौमिक गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकारों को जीडीपी का छह प्रतिशत तक खर्च करने की जरूरत है। अभी संयुक्त खर्च महज जीडीपी का 3.5 प्रतिशत ही किया जा रहा है। बजट में शिक्षकों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के साथ बुनियादी ढांचे के अंतर को भी पाटने की जरूरत है।

स्वस्थ तन सबसे बड़ा धन

संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकारों को जीडीपी का तीन प्रतिशत तक खर्च बढ़ाने की जरूरत है। सार्वभौमिक रूप से जरूरी दवाओं को सरकारी प्राथमिक केंद्रों में मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। जल एवं साफ-सफाई के क्षेत्र में पेयजल प्रोजेक्टों के ऑपरेशन और रख-रखाव के लिए बजट में व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा समुदाय के लिए जल स्रोतों के संरक्षण और विकास के लिए भी बजट में स्थान होना चाहिए।

रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र

परती/वर्षा आधारित खेती, वाटरशेड विकास प्रोजेक्टों, सूक्ष्म और लघु सिंचाई प्रोजेक्टों के लिए पर्याप्त आवंटन किया जाना चाहिए। खाद्य फसलों समेत कृषि फसलों को पूर्ण इंश्योरेंस कवर और 100 प्रतिशत प्रीमियम सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग (एनसीएफ) द्वारा सुझाए गए फार्मूले के आधार पर दिया जाना चाहिए। यह उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के मामले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सार्वभौमिक कर देना चाहिए। पीडीएस में खाद्यान्नों मसलन ज्वार, दलहन और खाद्य तेल को भी शामिल करना चाहिए। आपदा या सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए पीडीएस में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। 'सोशल ऑडिट' को संस्थागत कर पीडीएस को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

महिलाएं एवं बच्चे

विधानों के प्रभावी इस्तेमाल से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और संस्थागत प्रणाली को मजबूत करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

वंचित वर्ग

अनुसूचित जाति सब प्लान (एससीएसपी) तंत्र और आदिवासियों के लिए ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी) की सलाहकारी धाराओं को कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए। इनसे संबंधित फंड का ऑडिट हो। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (एफआरए), नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत) एक्ट के तेज क्रियान्वयन के लिए विशेष आवंटन किया जाना चाहिए। आदिवासी इलाकों के स्कूलों और स्वास्थ्य ढांचा के विकास के लिए राज्यों को अधिक फंड दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक वर्ग में विशेष रूप से मुस्लिमों में उद्यमशीलता के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खादी और बुनकरों को भी ऋण राहत उपक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रमों में सुधार करके और वित्तीय स्रोत सुविधाएं उपलब्ध कराके मजबूत बनाया जाना चाहिए।

असंगठित क्षेत्र

इस क्षेत्र के कामगारों के लिए स्थायी शरण और कार्यस्थलों पर बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए पर्याप्त फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी तरह अंतरराज्यीय वर्कमैन एक्ट के प्रावधानों को सभी असुरक्षित कामगारों पर लागू किया जाना चाहिए।

आंगनवाड़ी कर्मियों, आशा, मिड डे मील वर्करों को समुचित वेतन-भत्ते दिए जाने चाहिए।

बेतरतीब ढांचे में उम्मीद बेमानी

शिक्षा

● राजकेश्वर सिंह

सपने देखने-दिखाने में दशकों बीत गये। फिर भी पढ़ाई-लिखाई में सब कुछ बेतरतीब। सरकार का फिर एक बजट आने वाला है। उसमें भी बेहतरीन तालीम के कुछ सपने मन को बहलाने का जरिया बन सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता, उपलब्धता और कीमत का सवाल हल हुए बिना कुछ हासिल होने की बात बेमानी है।

एक नजर जरूर डालिए कि हम कहां हैं? टॉप 200 विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी शामिल नहीं है। देश में 22 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन उनमें से कॉलेज सिर्फ 70 लाख ही पहुंचते हैं। 11वीं व 12वीं के सिर्फ तीन प्रतिशत छात्र ही व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम अख्तियार कर रहे हैं। ऐसे में आज के युवा की पढ़ाई उसका कल कैसा बनाएगी, अंदाजा लगाया जा सकता है।

जरूरतों को पूरा करने में हम खड़े कहां हैं, जब अगले आठ साल में स्कूलों से कॉलेज पहुंचने वाले छात्रों की संख्या लगभग दोगुनी करनी है। सैकड़ों नये विश्वविद्यालयों के साथ ही कम से कम आठ-नौ सौ नए कॉलेजों की जरूरत होगी। मौजूदा 40 से 45 हजार कॉलेजों में सीटों की संख्या भी दोगुनी करनी होगी। आलम यह कि सरकार ने तो बीते महीनों में मौजूदा साल के लिए तय स्कूली शिक्षा के 25 हजार करोड़ के बजट में ही 2000 करोड़ की कटौती कर दी है। जबकि, जरूरत स्कूली शिक्षा बजट को दोगुना करने की है।

पढ़ाई की बड़ी गणित महंगाई से जुड़ी है। आइआइटी, आइआइएम जैसे संस्थानों की पढ़ाई महंगी हो रही है, जबकि निजी क्षेत्र की पढ़ाई तो और भी महंगी है। दूसरी तरफ संसाधनों के विस्तार व बाकी जरूरतों को पूरा करने में सरकार हकीकत से बहुत दूर खड़ी है। ऐसे में साफ है कि बगैर क्वालिटी, कीमत और उपलब्धता का सवाल हल किए और व्यावसायिक शिक्षा का रूट मजबूत किए वह शिक्षा की गाड़ी पटरी पर नहीं ला सकती।

ग्रोथ के अगले इंजन को चाहिए समुचित ईंधन

शहरी विकास

● आशुतोष झा

अध्ययन बताते हैं कि अगले दस वर्षों में साठ फीसद जीडीपी शहरों से आएगी। लेकिन उसके पहले निवेश की जरूरत होगी। जितना निवेश उतनी आमद।

भारत में फिलहाल लगभग 35 करोड़ आबादी शहरों में रह रही है जो अगले पंद्रह-सत्रह वर्षों में 60 करोड़ तक पहुंच जाएगी। पिछले दस वर्षों में शहरों के विकास के लिए जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण योजना के अलावा कुछ याद ही नहीं आता है। कुछ वर्ष पहले राजीव आवास योजना पर चर्चा जरूर शुरू हुई लेकिन अब तक कोई ठोस योजना नहीं बन पाई है। भारतीय शहरों और पूरे भारत के लिए सरकार की यह अनदेखी, उदासीनता और नीतिगत अभाव अभिशाप बनने लगी है। यह हाल तब है जबकि सरकार की ही ईशर विशेषज्ञ समिति के साथ साथ मैकेंजी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जरूरतें बहुत बड़ी है। हां, उसके साथ ही संभावनाएं भी अपार हैं। मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार अगले दस वर्षों में साठ फीसद जीडीपी शहरों से ही आएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2007 में विश्व की जीडीपी का आधा हिस्सा केवल 380 शहरों से आया था। यह वह शहर थे जो आर्थिक रूप से संपन्न होने के साथ साथ सामाजिक और ढांचागत स्तर पर भी समृद्ध हैं।

आशा की जा सकती है कि सरकार आवास और परिवहन की दो सबसे बड़ी समस्या पर जल्द ध्यान देगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत को अगले सत्रह वर्षों में लगभग 40 लाख करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

स्पष्ट नीति से बढ़ेगी विकास दर

ऊर्जा क्षेत्र

● जयप्रकाश रंजन

आंकड़ों में भले ही सरकार दावा करती हो कि उदारीकरण के बाद से देश की बिजली उत्पादन क्षमता ढाई गुना बढ़ चुकी है, कई विदेशी कंपनियों को भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खोज का ठेका जा चुका है, अभी तक का सबसे बड़ा गैस भंडार खोजा गया है आदि आदि। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पूरे देश में भयंकर बिजली कटौती होती है, कोयले की कमी से संयंत्र बिजली नहीं बना पा रहे, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता और बढ़ी है, आम आदमी पर महंगे पेट्रोलियम उत्पादों का बोझ बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं जिसमें देश की पूरी ऊर्जा अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती दिख रही है।

वैसे ऊर्जा क्षेत्र की अधिकांश दिक्कतों को बजट से दूर नहीं किया जा सकता फिर भी आगामी बजट से उम्मीद की जानी चाहिए। कम से कम सरकार इससे नीतिगत स्पष्टता लाने की कोशिश करेगी। बिजली क्षेत्र को पर्याप्त कोयला उपलब्ध कराने, कोयला ब्लाकों को पर्यावरण व वन संबंधी मंजूरी देने जैसे मुद्दों पर स्पष्ट नीति रखी जानी चाहिए।

चालू वित्त वर्ष के दौरान डीजल की कीमत बढ़ाने और सस्ते रसोई गैस सिलेंडर की सालाना संख्या को सीमित करने के बावजूद केंद्र सरकार पर वर्ष 2012-13 के दौरान 80 से 85 हजार करोड़ रुपये का सब्सिडी बोझ पड़ने के आसार हैं। राजकोषीय घाटे को 5.3 फीसद पर सीमित करने के रास्ते में यह एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में पेट्रोलियम सब्सिडी को लेकर एक स्पष्ट नीति की जरूरत है। चूंकि यह मसला सीधे तौर पर तेज आर्थिक विकास दर और युवा रोजगार से जुड़ा हुआ है। अगले दस वर्षों में दस करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए अर्थव्यवस्था में नौ फीसद की वृद्धि दर चाहिए। नौ या दस फीसद की वृद्धि दर के लिए हर ऊर्जा क्षेत्र में औसतन दस फीसद की विकास दर चाहिए।

कब दिखेगा सुधारने का साहस

बेहतर सेहत

● मुकेश केजरीवाल

अचानक आई बीमारी से लड़ने के लिए महंगी दवा खरीदने की मजबूरी लोगों को सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है। ऐसे में देश भर में मुफ्त दवा योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त धन मुहैया करवाना होगा। सभी राज्यों को इसके लिए खरीद, भंडारण और वितरण की ढांचागत व्यवस्था तैयार करने में मदद करनी होगी। इसी तरह केंद्रीय योजनाओं के लिए होने वाली खरीद प्रक्रिया को हर हाल में दुरुस्त करना होगा।

शहरी गरीबों की हालत गांव के लोगों से भी बदतर है। तीन साल से लटके पड़े शहरी स्वास्थ्य मिशन को शुरू करना बेहद जरूरी होगा। जच्चा और बच्चा की सेहत के लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तो शुरू किया गया, मगर इस साल देश भर में इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। अब सरकार को यह गारंटी देनी होगी कि एक भी बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं होगा।

देश में सिर्फ छह एम्स काफी नहीं। जीवनशैली संबंधित बीमारियों की तरफ अतिरिक्त ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य में हमारा शोध आज भी पिछड़ा हुआ है। पर्याप्त बजटीय प्रावधान के साथ इसे प्राथमिकता में लाने की जरूरत है।

बड़ी अपेक्षा वाला क्षेत्र उपेक्षा का शिकार

सबको भोजन

● सुरेंद्र प्रसाद सिंह

खेती के सामने जहां भूख से निपटने की चुनौती है, वहीं खाद्य उत्पादों की महंगाई को थामने की मुश्किलें भी। इन बुनियादी जरूरतों के लिए खेती से पर्याप्त उपज की अपेक्षा तो है, लेकिन तमाम समस्याओं से जूझ रही खेती खुद उपेक्षा की शिकार है। पिछले कुछ साल में खेती की लागत बढ़ने से महंगाई का बड़ा हिस्सा खेतों के रास्ते रसोई में घुस चुका है।

निरंतर घटते संसाधनों के बीच खेती जलवायु परिवर्तन की मार झेल रही है। कृषि वैज्ञानिकों की मानें तो तापमान में वृद्धि के चलते गेहूं व चावल की उत्पादकता में कमी आना तय है। इसके विपरीत जनसंख्या और जीवन स्तर में सुधार से खाद्यान्न की मांग बढ़ रही है।

ऐसे में खेती पर दोहरा बोझ है। लागत में वृद्धि होने से खाद्य उत्पादों की महंगाई से उपभोक्ता हलकान है। दूसरी तरफ फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाने की वजह से खेती के प्रति निराशा बढ़ी है।

चुनावी साल के लिए पेश होने वाले आम बजट में सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित कराने की जुगत में है। लेकिन इसके लिए सालोंसाल जितने अनाज की जरूरत पड़ेगी, खेती उसके लिए कतई तैयार नहीं है।

आम बजट में खेती को बहुत कुछ मिलेगा, इसकी संभावना कम ही है। उसकी सभी योजनाओं में 15 फीसद की कटौती की घोषणा पहले ही कर दी गई है। सरकार ने परंपरा से हटकर थोड़ा सा ध्यान दिया तो खाद्यान्न रखने के लिए गोदाम कम पड़ गए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ दूसरी हरितक्रांति की पहल से खेती को बल मिला है। लेकिन खेती का दो तिहाई हिस्सा आज भी असिंचित यानी बारिश पर निर्भर है। खाद्यान्न की मांग को पूरा करने के लिए खेती की पैदावार में कई गुना की वृद्धि होनी चाहिए।

जनमत

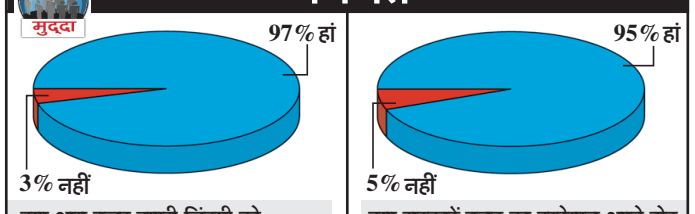

क्या आम बजट हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है?

क्या सरकारें बजट का इस्तेमाल अपने वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए करती हैं?

आपकी आवाज

जिस तरह रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की कीमतों में हर एक या दो महीने बाद ही वृद्धि होती रहती है, उससे तो यह लगता है कि हर महीने देश का आम बजट बनता है
-राजू 09023693142@जीमेल.कॉम

सरकार बजट में जो घोषणाएं करती है, उनका सीधा सरोकार वोट बैंक को साधना होता है। बाद में चाहे उन घोषणाओं पर काम हो या न हो -शुभम जीपीटी 100@जीमेल.कॉम

सरकार को अपने अंतिम बजट में ही लुभावनी योजनाएं बनाने की याद आती है। ताकि अपना वोट बैंक बढ़ाने में उसे मदद मिल सके
-के देवेंद्र 06@जीमेल.कॉम

हमेशा से ही बजट का इस्तेमाल वोटबैंक को प्रभावित करने के लिए होता आया है। इस बार तो लोकसभा के अलावा राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं
-मुन्ना कुमार 85@याहू.कॉम